



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

No. 183]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/12/2003-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा 20 टन ग्रैब बंदरगाह क्रेन के वर्तमान किराया प्रभारों की वैधता को आगे बढ़ाने के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/12/2003-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

1.1. इस प्राधिकरण ने तृतीकोरिन पत्तन न्यास की तीन 20 टन ग्रैब बंदरगाह क्रेनों हेतु छह माह की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर प्रभार निर्धारित करते हुए 17 मार्च, 2003 को एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश 12 अप्रैल, 2003 को राजपत्र सं. 52 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण ने टीपीटी के दरमान में निम्नलिखित प्रावधानों को, 30 सितम्बर, 2003 तक वैध बने रहने के लिए, सम्मिलित किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया था :

- (i) मान 5.2.2. - मास्टरों, स्वामियों अथवा जलयानों के एजेंटों के लिए बंदरगाह क्रेनों और अन्य यांत्रिक उपकरणों के किराया प्रभार :

"20 टन (ग्रैब) बंदरगाह क्रेन के उपयोग पर 9,636/- रुपए प्रति पारी और 4,818/- रुपए प्रति आधी पारी अथवा उसका हिस्सा।"

- (ii) मान 5.3. - अनुसूची 5.2.1. और 5.2.2. में अधिनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए क्रेनों, फोर्क लिफ्ट ट्रकों और अन्य यांत्रिक उपकरणों के किराया प्रभार :

क्र.सं. 7 - बंदरगाह ग्रेब क्रेन - (20 टन) - 3308/- रुपए प्रति घंटा अथवा उसका हिस्सा।

"बंदरगाह क्रेन (10 टन और उससे कम) - 295/- रुपए प्रति घंटा अथवा उसका हिस्सा।

"उन लंगरगाहों के लिए जहां नई 20 टन क्रेनों संस्थापित हैं, टीपीटी को बिना क्रेन वाले लंगरगाहों पर लागू लंगरगाह किराया प्रभार वसूल करना चाहिए बशर्त लंगरगाह किराया प्रभारों की वसूली के बदले में वहां किसी अन्य बंदरगाह क्रेन की आपूर्ति नहीं की जाती हो।"

1.2. उक्त आदेश में, टीपीटी को, 1 अक्टूबर, 2003 से आगे लागू होने वाली संशोधित दरें निर्धारित करने के लिए, प्रचालन में प्राप्त अनुभव के आधार पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया था।

2. उक्त आदेश के संदर्भ में, टीपीटी ने अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2003 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से 20 टन ग्रेब क्रेन के वर्तमान किराया प्रभारों की वैधता को 31 मार्च, 2004 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। टीपीटी ने वर्तमान दरों की वैधता आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कारण दिए हैं :

- (i) विचाराधीन क्रेन औपचारिक रूप से 11 जनवरी, 2003 से शुरू की गई थी और 19 फरवरी, 2003 तक की अल्पावधि के लिए कार्गो प्रहस्तन हेतु उपलब्ध करवाई गई थी।
- (ii) कार्गो प्रहस्तन कार्य के दौरान, सभी तीनों नई ग्रेब क्रेनों के लफ गियर बॉक्स में खराबी आ गई थी और इसलिए क्रेन के आपूर्तिकर्ता से सभी खराबियों को ठीक करने के पश्चात इन क्रेनों को पुनः शुरू करने का अनुरोध किया गया था। प्रभावी कार्गो प्रहस्तन कार्य के लिए इन क्रेनों की तैनाती अभी की जानी है।
- (iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा पत्तन को क्रेनों के औपचारिक हस्तांतरण किए जाने के पश्चात ही यह पत्तन, प्रचालन से होने वाले अनुभव के आधार पर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति में होगा। उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान दर को 31 मार्च, 2004 तक जारी रखने की अनुमति दी जाए।

3. टीपीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 टन ग्रेब बंदरगाह क्रेन के लिए प्रस्तावित दर केवल ग्रेब के लिए वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त प्रभार है। इसने स्पष्ट किया है कि ग्रेब को छोड़कर बंदरगाह क्रेन प्रभार को लंगरगाह किराया प्रभार के साथ मिला दिया गया है। इसलिए टीपीटी में जहां 20 टन ग्रेब बंदरगाह क्रेन उपलब्ध कराई गई है, वहां क्रेन रहित लंगरगाह किराया प्रभार की वसूली निर्धारित करने वाले खंड को हटाने का अनुरोध किया है।

4.1. यहां यह दोहराना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा इस मामले में पहले निर्धारित किए गए किराया प्रभार लागत आधारित नहीं है अपितु 10 टन ग्रेब क्रेनों की (तत्कालीन) प्रचलित दरों से लिए गए हैं। ये दरें नई क्रेनों और उसकी पुरानी क्रेनों की (संभावित) निष्पादनता की तुलना करके आकलित की गई थीं। चूंकि नई क्रेनों द्वारा अर्जित सतत औसत आउटपुट/निष्पादनता के ब्योरे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए प्रस्तावित दरों को उनकी वैधता छह माह की अवधि तक सीमित रखते हुए तदर्थ आधार पर अनुमोदित किया गया था। उस अवधि के दौरान प्रचालन से प्राप्त अनुभव के संदर्भ में, छह माह की अवधि के पश्चात तदर्थ दरों की समीक्षा करने की योजना थी। जैसे ही यह कार्यान्वित हुआ, क्रेनों ने केवल लगभग 40 दिन कार्य किया ; और, इसीलिए, समीक्षा करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में, पत्तन द्वारा किए गए अनुरोधानुसार, वर्तमान तदर्थ प्रभारों को 1 अक्टूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति देना अपरिहार्य है।

4.2. पहले से लिए गए सामान्य नीति निर्णय के अनुसार तदर्थ दर उच्चतम दर होगी। 31 मार्च, 2004 के पश्चात यह दर स्वतः ही लागू होना बंद हो जाएगी। टीपीटी को, प्रचालन से होने वाले अनुभव के आधार पर तैयार किया जाने वाला अपना प्रस्ताव किसी भी स्थिति में 15 फरवरी, 2004 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ताकि यह प्राधिकरण 31 मार्च, 2004 से आगे लागू होने वाली संशोधित दरें निर्धारित कर सके।

4.3. जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, 20 टन ग्रेब क्रेन के तदर्थ प्रभार दरमान में मौजूद 10 टन ग्रेब क्रेनों की दरों से तुलना करके निर्धारित किए गए थे। चूंकि क्रेन प्रभार घटक लंगरगाह किराया प्रभारों में शामिल है, टीपीटी के दरमान में बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के, जलयानों की लदाई और उतराई के लिए बंदरगाह क्रेनों की आपूर्ति का प्रावधान है। इसलिए, टीपीटी ने तर्क दिया है कि दरमान में उपलब्ध 10 टन ग्रेब क्रेन की दर ग्रेब के उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रभार था जोकि प्रभार्य लंगरगाह किराये के हिस्से के रूप में क्रेन की आपूर्ति के अतिरिक्त होना चाहिए। 10 टन ग्रेब क्रेनों के लिए निर्धारित 1912/- रुपए प्रति घंटा प्रभार की मात्रा पर विचार करने पर टीपीटी के तर्क में

दम लगता है। ऐसी स्थिति में, क्रेन रहित लंगरगाहों के लिए लागू लंगरगाह किराया लगाने के बारे में इस प्राधिकरण द्वारा लागू की गई शर्त प्रासंगिक नहीं पाई गई है और इसलिए हटाई जाती है। तथापि, टीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव तैयार करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और 20 टन ग्रेब ग्रेनों के प्रभारों के परिकलन के लिए केवल उपयुक्त लागतों पर ही विचार करना चाहिए।

5. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदन करती है :

- (i) दिनांक 17 मार्च, 2003 के आदेश द्वारा निर्धारित तदर्थ प्रभार, 1 अक्तूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए उच्चतम दरों के रूप में जारी रहेंगे।
- (ii) उन लंगरगाहों के लिए जहां संदर्भित 20 टन ग्रेब बंदरगाह क्रेनें संस्थापित हैं, वहां क्रेन रहित लंगरगाह के लागू लंगरगाह किराया प्रभार की वसूली विनिर्दिष्ट करने वाले उपबंध को हटाया जाना।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/IV/143/2003-असा. ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2003

**No. TAMP/12/2003-TPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Tuticorin Port Trust for extending the validity of the existing hire charges of 20T grab wharf crane as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE Case No. TAMP/12/2003-TPT

The Tuticorin Port Trust

----

Applicant

### ORDER

(Passed on this 22nd day of October 2003)

1.1. This Authority had passed an Order on 17 March 2003 fixing charges for three 20 T grab wharf cranes of the Tuticorin Port Trust (TPT) on an adhoc basis for the period of six months. The said Order was notified in the Gazette of India on 12 April 2003 vide Gazette Number 52. This Authority approved inclusion of the following provisions in the Scale of Rates of the TPT to remain valid upto 30 September 2003:

- (i). *Scale 5.2.2 – Charges for hire of wharf cranes and other mechanical equipments to masters, owners or agents of vessels:*

*“Use of 20 T (Grab) wharf crane Rs.9,636/- per shift and Rs.4,818/- per half shift or part thereof.”*

- (ii). *Scale 5.3. - Charges for hire of cranes, fork lift trucks and other mechanical appliances for purposes not specified in Schedule 5.2.1. and 5.2.2.*

*Sl. No. 7 – Wharf Grab Cranes (20 Tonne) – Rs 3308/- per hour or part thereof.*

*"Wharf Crane (10 tonnes and below) – Rs.295/- per hour or part thereof."*

*"For those berths where the new 20T cranes are installed, the TPT should levy berth hire charges applicable for non-crane berths provided no other wharf crane is supplied thereat against the levy of berth hire charges."*

1.2. In the said Order, the TPT was advised to submit its proposal based on the experience gained in operation for fixing the revised rates applicable beyond 1 October 2003.

2. With reference to this Order, the TPT vide its letter dated 6 October 2003 has requested this Authority to extend the validity of the existing hire charges for 20T grab crane till 31 March 2004. The TPT has given the following main reasons for extension of the existing rates:

- (i). The subject cranes were formally commissioned on 11 January 2003 and were spared for handling cargo for a short period upto 19 February 2003.
- (ii). During the cargo handling operation, there was a problem in luff gear box on all the three new grab cranes and hence the supplier of the crane was requested to re-commission these cranes after rectifying all the defects. These cranes are yet to be deployed for effective cargo handling operation.
- (iii). The port will be in a position to submit revised proposal based on the experience gained in the operation only after the cranes are formally handed over by the supplier to the port. In the light of the above, the existing rate may be allowed to continue up to 31 March 2004.

3. The TPT has also clarified that the rate proposed for 20T grab wharf crane is the extra charge to be levied for grab alone. It has clarified that wharf crane charge excluding grab is merged with the berth hire charge. The TPT has, therefore, requested to delete the clause prescribing levy of non-crane berth hire charge where the 20T grab wharf crane are provided.

4.1. It may be relevant here to recall that the hire charges in this case fixed earlier by this Authority are not cost based rates but derived from the (then) existing rates for 10 T grab cranes. The rates were derived by comparing (likely) performance of the new crane with that of the old crane. Since details of sustained average output / performance achieved by the new cranes were not available, the proposed rates were approved on an adhoc basis limiting the validity for six months. The idea was to review the adhoc rates after six months' time with reference to the experience gained in operation during that period. As it turned out, the cranes worked only for about 40 days; and, therefore, no sufficient data is available to take up a review. That being so, it is inevitable to allow the present adhoc charges to continue for a further period from 1 October 2003 to 31 March 2004, as requested by the port.

4.2. The adhoc rate will be a ceiling rate in line with the general policy decision already taken. This rate will automatically cease to apply after 31 March 2004. The TPT is advised to submit its proposal to be framed based on the experience gained in operation, in any case not later than 15 February 2004 to enable this Authority to fix the revised rates applicable beyond 31 March 2004.

4.3. As has been mentioned earlier, the adhoc charges for 20 T grab crane were fixed by comparing the rates existed in the Scale of Rates for 10 T grab cranes. The Scale of Rates of the TPT provides for supply of wharf cranes for loading and unloading of vessels without any extra charge since crange element is included in berth hire charges. The TPT has, therefore, argued that the rate for 10 T grab crane available in the Scale of Rates was an

additional charge for use of the grab which should be over and above the supply of crane as a part of berth hire leviable. Considering the quantum of charge of Rs.1912/- per shift prescribed for the 10 T grab cranes, the argument of TPT appears to carry force. That being so, the condition introduced by this Authority about levying berth hire as applicable for non crane berths is not found to be relevant and is deleted. While formulating its revised proposal, the TPT should, however, bear this aspect in mind and consider only the relevant costs for computation of charges for 20 T grab cranes.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following:

- (i). The adhoc charges fixed vide Order dated 17 March 2003 to continue as ceiling rates for a further period from 1 October 2003 to 31 March 2004.
- (ii). Deletion of the provision stipulating levy of berth hire charge as applicable for non-crane berths for berths where 20T grab wharf cranes in reference are installed.

A. L. BONGIRWAR, Chairman  
[ADVT III/IV/143/2003-Exty.]